हिन्दी साप्ताहिक

R.N.I. No. UPHIN/2022/83621

जनता का सच

वर्ष 05 अंक 27 | लखनऊ शनिवार 11 जुलाई 2026 | पृष्ठ 04 मूल्य 2 रूपया

राममंदिर चढ़ावा चोरी : दान गिनने वाले 23 कर्मचारियों का इस्तीफा

चढ़ावे में 10-20 के नोट बढ़े, 500 के घटे ; सुप्रीम कोर्ट में 13 जुलाई को सुनवाई

लखनऊ , सववंवाददाता। अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच 3 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। याचिकाओं में जांच छ्वढ्ढ को सौंपने और स्ढ्ढञ्ज के गठन के मांग की गई है। साथ ही, मंदिर में दान के प्रबंधन से जुड़े अलग-अलग विषयों की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने की भी मांग की गई है। इधर, मंदिर में चढ़ावा गिनने वाले 23 कर्मचारियों ने गुरुवार को एक साथ इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि चोरी की घटना के बाद 10-20 रुपए के नोट बढ़ गए हैं, जिससे गिनती में ज्यादा समय लग रहा है। पहले 500 रुपए के नोटों की 70-80 गड्डियां बन जाती थीं, अब बमुश्किल 15 गड्डियां बन रही हैं। पहले काम दो शिफ्ट में होता था, लेकिन अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक एक ही शिफ्ट कर दी गई है। वेतन वही है और काम के घंटे बढ़ गए हैं। अब बैंक के पास सिर्फ 13 गणना कर्मी बचे हैं।चढ़ावा चोरी से माता सीता का मायका जानकी मंदिर भी आहत है। श्रीराम का ससुराल पड़ोसी देश नेपाल के जनकपुर में है। मंदिर के महंत रोशन दास ने कहा कि भगवान श्रीराम के किसी मंदिर में ऐसी घटना न कभी देखी, न सुनी। मन व्यथित है, इसलिए सावन में जनकपुर से 5-7 लोग प्रभु श्रीराम के घर अयोध्या जाएंगे। सांत्वना देंगे और दर्शन कर लौट आएंगे। सीएम योगी ने शुक्रवार को बस्ती जिले के हरैया में सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा- पहले जो पैसा कब्रिस्तानों में खर्च होता था, वह अब भदेश्वर और तपसी धाम में लगाया जा रहा है। पहले वक्फ बोर्ड के नाम पर पैसा लूटा जाता था। सपा, बसपा और कांग्रेस वक्फ के नाम पर गरीबों को उजाड़ते थे। हमने उन्हें बसाने का काम किया है। उन्होंने कहा- ये रामभक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का काम सपाइयों ने किया था। कर्ण मंदिर का विवाद भी सपाइयों ने ही खड़ा किया था। ये डराते थे कि अयोध्या में मंदिर बना तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा था कि एक मच्छर भी नहीं मरेगा। सुमेरपुर में हमने भगवान राम और निषादराज की प्रतिमा स्थापित कराकर वहां का सौंदर्यीकरण कराया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा- राम मंदिर के अंदर जो डकैती हुई है, भाजपा के नेता, भाजपा की सरकार और ऋस्स् के नेताओं के बिना ये संभव नहीं हो सकता। इसमें सभी लोग शामिल हैं। अगर ईमानदारी के साथ जांच होती तो इसमें पता नहीं कितने बड़े लोगों के नाम आ जाते। यही कारण है कि प्रधानमंत्री खामोश हैं। प्रधानमंत्री, जो सुबह-शाम भगवान राम का नाम लेते हैं, वहां(राम मंदिर) डकैती पड़ रही है तो खामोश हैं? उत्तर प्रदेश की स्ढ्ढञ्ज, स्ढ्ढञ्ज नहीं है बल्कि नेताओं को बचाने के लिए एक समिति है। मैं बार-बार कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की देख-रेख में एक जांच समिति बननी चाहिए।

डबल इंजन सरकार आई तो राम मंदिर बना: योगी आदित्यनाथ

सीएम योगी ने बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में 217 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण/शिलान्यास

अयोध्या , संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आस्था का दिखावा करने वाले दलों पर रामनगरी में कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई थी, लेकिन क्या सपा, कांग्रेस या अन्य सरकारें जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करवा पाएंगी। यदि नहीं करा पाएंगी तो हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों कराया गया था? आस्था का दिखावा कर रहे लोगों ने यह पाप किया था, जबकि भाजपा ने अयोध्या को सनातन धर्म की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्थापित किया। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में 432 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास किया। इस अवसर पर अयोध्या के विकास कार्यों पर आधारित लघु फिल्म भी दिखाई गई। मुख्यमंत्री ने यहां पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण भी किया और लोकार्पण व शिलान्यास वाली तमाम योजनाओं का जिक्र कर इनका श्रेय जनता व जनप्रतिनिधियों को दिया। सीएम ने कहा कि बीकापुर विधायक ने पिछली बार ग्राम पंचायत खिरौनी-सुचित्तागंज को नगर पंचायत बनवाया था। अब उनकी मांग पर यह नगर पंचायत मां ज्वाला देवी के नाम पर होगी। समाजवादी पार्टी का असली चरित्र सभी ने देखा होगा, जब इनके नमूने चेयरमैन ने भदरसा में गुस्ताखी की थी। भदरसा नगर पंचायत अब भरतनगर भरतकुंड होगा। भाई-भाई का संबंध भरत जी से सीखिए। 14 वर्ष तक भरतकुंड के पास रहकर उन्होंने

भगवान राम की आज्ञा का पालन किया। भगवान राम की चरण पादुकाएं अयोध्या का संचालन कर रही थीं। भरत जैसा भाई मिलना मुश्किल है, लेकिन अयोध्या में राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न जैसे भाई हुए। चारों दिशाओं में अयोध्या की पहचान आज भी मौजूद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीयत साफ और नीति स्पष्ट हो तो नियंता भी साथ देता है। प्रभु राम और पवनसुत के आशीर्वाद से सभी कार्य अपने आप बढ़ते हैं। बीकापुरवासियों ने अच्छा विधायक चुना तो विकास दौड़ता दिखाई देता है। जैसे अयोध्या का वैभव देश में चरम पर दिखाई देता है, वैसे ही बीकापुर में भी विकास की योजनाएं दिखाई दे रही हैं। सक्रिय जनप्रतिनिधि जब विकास में रूचि लेते हैं तो परिणाम वैसे ही सकारात्मक आते हैं, जैसे आज अयोध्या, बीकापुर, मिल्कीपुर, गोसाईगंज, रुधौली में दिखाई दे रहे हैं। सीएम ने कहा कि 19 जून को हमने रुदौली में विकास योजनाओं की सौगात दी थी। पहले जो असंभव था, वह इन जनप्रतिनिधियों के कारण संभव हो पाया। लंबे समय तक सड़क, बिजली, पानी नहीं मिलने से अयोध्या उपेक्षित होने के साथ विकास से वंचित रहती थी। व्यवस्था न होने से श्रद्धालु मां सरयू का आशीर्वाद लेने में विफल रहता था, लेकिन अब मां सरयू की पवित्र धारा अयोध्या को अभिसिंचित करती है। सीएम ने कहा कि अयोध्या अब वैभवशाली और तीनों लोकों से न्यारी है। गलियां चमक रही हैं, लाइट भी रहती है। सूर्यवंश की राजधानी अयोध्या पीएम मोदी के विजन के अनुरूप सोलर सिटी बन गई है। नए घाट से लेकर गुप्तार घाट तक घाटों की श्रृंखला है। सीएम ने सभी का आह्वान किया कि कभी उपेक्षित रहे गुप्तार घाट में अब परिवार के साथ घूमने जाइए। हमने सूरजकुंड का पुनरुद्धार किया। स्थानीय विधायक के प्रस्ताव पर भरतकुंड का सौंदर्यीकरण भी हो रहा है।सीएम ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग एयरपोर्ट के नाम पर गुमराह करते थे, लेकिन अब महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। अयोध्या सभी शहरों के साथ जुड़ गई है। सपा व कांग्रेस वाले कुछ नहीं कर पाए, इसलिए अयोध्या का विरोध कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार ने निषादराज के नाम पर रैनबसेरा और मां शबरी के नाम पर भोजनालय बनवाकर समरसता फैलाई। हरिद्वार में हरि की पैड़ी की तरह ही अयोध्या में राम की पैड़ी दिख रही है। रोज सरयू मैया की आरती होती है। सपा जिस वक्फ के नाम पर श्रृंग्वेरपुर में कब्जा करा रही थी, भाजपा सरकार ने वहां भगवान राम व निषादराज के मिलन की भव्य प्रतिमा व स्मारक बनाया है। सपा के लोग जाकर देखें कि श्रृंग्वेरपुर सौंदर्यीकरण की नई ऊंचाइयों तक पहुंच गया है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस व सपा ने मंदिर निर्माण में बाधाएं डालीं, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा किया। रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं, लेकिन डबल इंजन सरकार आई तो राम मंदिर बन गया। अयोध्या आने वाला हर व्यक्ति अब अभिभूत होकर जाता है। भक्ति पथ, धर्मपथ, रामपथ, जन्मभूमिपथ अयोध्या की पहचान बन रहे हैं। सिंगल लेन की जगह अब फोरलेन व सिक्स लेन हैं। एयर, रेल व रोड कनेक्टिविटी अयोध्या को नई पहचान दिला रही है। बीकापुर, रुदौली, मिल्कीपुर व गोसाईगंज को भी लाभ प्राप्त हो रहा है।

जिला पंचायत अध्यक्ष बने प्रशासक

नई पंचायतों के गठन तक संभालेंगे जिमेदारी

लखनऊ,संवाददाता। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने से ठीक पहले बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। पंचायती राज विभाग ने शुक्रवार को जारी कार्यालय ज्ञापन के जरिए प्रदेश के सभी मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्षों को उनके-अपने जिले का प्रशासक नियुक्त कर दिया है। यह व्यवस्था नई जिला पंचायतों के गठन और नव-निर्वाचित अध्यक्षों के कार्यभार संभालने तक प्रभावी रहेगी। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार वर्ष 2021 में गठित जिला पंचायतों का कार्यकाल 11 जुलाई 2026 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में 12 जुलाई 2026 से नई जिला पंचायतों के गठन अथवा अधिकतम छह माह की अवधि तक, जो पहले हो, वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासक के रूप में सामान्य प्रशासनिक कार्यों का संचालन करेंगे। कार्यालय ज्ञापन में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की विभिन्न धाराओं का हवाला देते हुए कहा गया है कि यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में समय पर नई जिला पंचायतों का गठन संभव नहीं हो पाता है तो सरकार प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकती है। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रशासक के रूप में नियुक्त जिला पंचायत अध्यक्ष केवल रूटीन और सामान्य प्रशासनिक कार्य ही करेंगे। वे किसी प्रकार के नीतिगत या बड़े वित्तीय निर्णय नहीं ले सकेंगे। यदि किसी विशेष परिस्थिति में नीतिगत निर्णय की आवश्यकता होगी तो संबंधित प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजा जाएगा और शासन की मंजूरी के बाद ही उस पर निर्णय होगा। सरकार ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और जिला मजिस्ट्रेटों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश का उद्देश्य जिला पंचायतों में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखना और नई पंचायतों के गठन तक विकास कार्यों तथा नियमित प्रशासनिक गतिविधियों में किसी प्रकार का व्यवधान न आने देना बताया गया है। इस फैसले के साथ प्रदेश की सभी जिला पंचायतों में सत्ता का संक्रमण सुचारु रूप से सुनिश्चित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। अब सभी की निगाहें आगामी जिला पंचायत चुनाव और नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया पर टिकी हैं।

गडकरी ने की गुजरात के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा

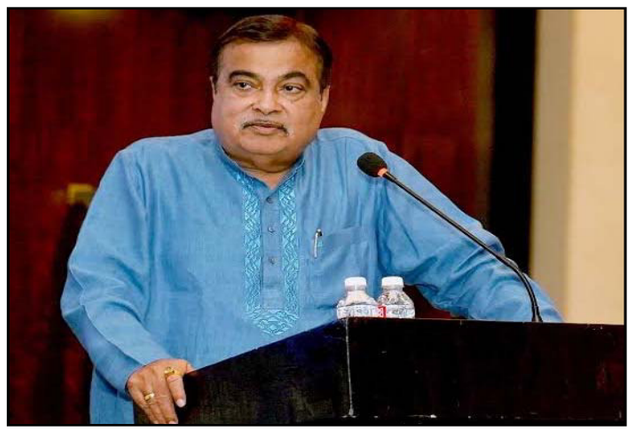

गांधीनगर, (एजेंसी)। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाइवे) परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। राज्य सूचना विभाग ने अपने बयान में बताया कि इस बैठक में नवंबर 2025 में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद हुई प्रगति की जानकारी मुख्य सचिव एम.के. दास और मुख्यमंत्री के सलाहकार एस.एस. राठौड़ ने प्रस्तुत की। इस पर केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इसके प्रस्तुतीकरण के दौरान वडोदरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के सिक्स लेन कार्य, मोरबी-सामाखियाली मार्ग के सामाखियाली-मालिया सेक्शन, राजकोट-गोंडल-जेतपुर रोड, अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद-गोधरा-इंदौर रोड, जामनगर-अमृतसर एक्सप्रेसवे, पालनपुर-सामाखियाली कॉरिडोर तथा अहमदाबाद-शामलाजी सिक्स लेन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेस वे को भावनगर तक विस्तारित करने का कार्य अगले तीन महीनों में शुरू किया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार से केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव शीघ्र केंद्र सरकार को भेजने का भी अनुरोध किया। गडकरी ने डीपीआर तैयार होने के दौरान सड़क अलाइनमेंट में आने वाली भूमि के अधिग्रहण को आसान बनाने के लिए गैर-कृषि (एनए) अनुमति की प्रक्रिया 60 दिनों तक स्थगित रखने की गुजरात सरकार की व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि यह %गुजरात मॉडल% पूरे देश के लिए अनुकरणीय बन सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पर्यावरण-अनुकूल विकास के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए निर्देश दिया कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान मार्ग में आने वाले पेड़ों को काटने के बजाय उन्हें उसी सड़क के किनारे अन्य स्थान पर प्रतिरोपित कर विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय के कारण भूमि अधिग्रहण सहित सड़क अवसंरचना परियोजनाओं में तेजी आई है।

सीएम रेखा गुप्ता ने गडकरी से मांडी रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की अपील की

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर दक्षिण दिल्ली के मांडी रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने और इसके विकास का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को सौंपने की अपील की। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि लगभग 8.8 किलोमीटर लंबा मांडी रोड दिल्ली-एनसीआर का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सड़क गलियारा है। यह छतरपुर मेट्रो स्टेशन के निकट महरौली-गुरुग्राम रोड (एनएच-148ए) को दिल्ली-हरियाणा सीमा पर गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड से जोड़ता है। यह मार्ग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पड़ोसी आर्थिक केंद्रों गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क कड़ी के रूप में कार्य करता है तथा अंतर-राज्यीय यातायात के सुचारु संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सरकार का आदेश- पहले वंदे मातरम् फिर जन-गण-मन होगा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगान जन-गण-मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम् को लेकर सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों को नए निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि नियमों में पहले से तय है कि किन कार्यक्रमों में दोनों को गाना या बजाना जरूरी है। मंत्रालय ने कहा कि एक ही कार्यक्रम में दोनों में से पहले वंदे और फिर जन-गण-मन होगा। जिन राज्यों में राज्य गीत होता है, वहां भी सीक्वेंस का पालन करना होगा। 9 जुलाई को सभी राज्यों और मंत्रालयों को पत्र भेजा गया, जिसकी जानकारी शुक्रवार को सामने आई है। सभी राज्यों से कहा गया है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हमेशा उनके असली शब्दों, सही उच्चारण और तय नियमों के अनुसार ही गाया और बजाया जाए। इसके लिए दोनों की ऑफिशियल कॉपी मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई है।भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी पर लिखा था। यह 1882 में पहली बार उनकी पत्रिका बंगदर्शन में उनके उपन्यास आनंदमठ के हिस्से के रूप में छपा था। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर ने मंच पर वंदे मातरम गाया।

वंदे मातरम् ने देशभक्ति को राष्ट्रीय कर्तव्य बनाया : उपराष्ट्रपति

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम् ने मातृभूमि के प्रति प्रेम को पवित्र राष्ट्रीय कर्तव्य में बदल दिया और इसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असंख्य सेनानियों को साहस, त्याग और आशा से प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने केवल रियासतों का ही नहीं, बल्कि देशवासियों के दिलों का भी एकीकरण किया और एक राष्ट्र, एक संविधान तथा साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी। उपराष्ट्रपति शुक्रवार को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी (आईआईएएस), शिमला द्वारा आयोजित 'वंदे मातरम् की यात्रा' पर स्थायी प्रदर्शनी के उद्घाटन तथा 'सरदार पटेल का विजन - एकीकरण, एकजुटता और संघवाद' विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को आभासी माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम- केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्र चेतना का प्रतीक है। इसने देशभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की। उन्होंने कहा कि आज भी यह गीत राष्ट्र के प्रति समर्पण, आत्मगौरव और राष्ट्रीय एकता का प्रेरक स्रोत बना हुआ है।

डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर जोर

एबीडीएम की प्रगति की समीक्षा

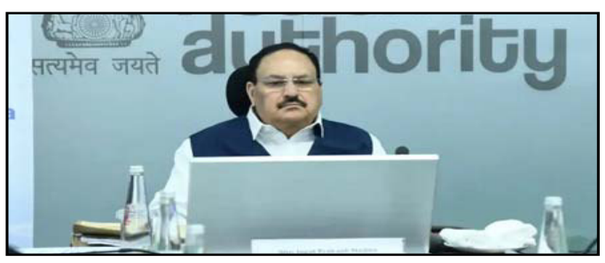

नई दिल्ली एजेंसी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए देश में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और मिशन की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एबीडीएम के तहत मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना तैयार की जा चुकी है, लेकिन अब अगले चरण में इसका व्यापक स्तर पर उपयोग सुनिश्चित करना होगा, ताकि प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित, सरल और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।नड्डा ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाना विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इस दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ सभी संबंधित पक्षों से मिलकर नागरिकों को निर्बाध, सुरक्षित और नागरिक-केंद्रित डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में शामिल हो चुका है। अब तक 93.95 करोड़ से अधिक एबीएचए (आभा) नंबर जारी किए जा चुके हैं, जबकि 105 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप से लिंक किए गए हैं। इसके अलावा 5.33 लाख स्वास्थ्य संस्थान और 9.85 लाख स्वास्थ्य पेशेवर राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य रजिस्ट्री में पंजीकृत हैं। अधिकारियों के अनुसार देशभर में 2.72 लाख स्वास्थ्य संस्थानों ने एबीडीएम सॉफ्टवेयर को अपनाया है। ओपीडी पंजीकरण को आसान और तेज बनाने के लिए लगभग 24 करोड़ 'स्कैन एंड रजिस्टर' टोकन जारी किए गए हैं। इसके माध्यम से मरीज अपनी सहमति के आधार पर विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में अपने डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड का सुरक्षित उपयोग कर सकते हैं। बैठक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मिशन के विस्तार, सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के बेहतर एकीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी नई तकनीकों के उपयोग तथा डिजिटल स्वास्थ्य मानकों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विस्तार से चर्चा हुई। संचालन समूह ने मॉडल जिलों और मॉडल स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के प्रयासों की सराहना की। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ.माणिक साहा, मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, अनुप्रिया पटेल, जितिन प्रसाद, नीति आयोग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, आयुष मंत्रालय तथा विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के तीसरे चरण में न्यूजीलैंड पहुंचे, एयरपोर्ट पर पीएम लक्सन ने किया स्वागत

नई दिल्ली,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी यात्रा के तीसरे चरण में शुक्रवार को न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड पहुंचे जहां एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने उनके अगले गंतव्य पर पहुंचने की जानकारी एक्स पर साझा की।उन्होंने बताया, ÷कुछ देर पहले ऑकलैंड पहुँच गया हूँ। हवाई अड्डे पर स्वागत के लिए प्रधानमंत्री लक्सन का आभारी हूँ। यह यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि चार दशकों में यह पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड का दौरा कर रहा है। मैं प्रधानमंत्री लक्सन से बातचीत करने और भारत-न्यूजीलैंड मित्रता के सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हूँ। मैं कल ऑकलैंड में एक सामुदायिक कार्यक्रम को भी संबोधित करूँगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री दो देशों की यात्रा कर दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचे हैं। यह चार दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की पहली आधिकारिक यात्रा है। ऑकलैंड में प्रधानमंत्री लक्सन के साथ वे द्विपक्षीय चर्चा करेंगे और संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। समीक्षा में पिछले दो वर्षों में व्यापार, वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।ऑकलैंड में अपने प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री प्रमुख व्यापार और खेल जगत की हस्तियों से भी बातचीत करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री इस यात्रा के दौरान प्रवासी भारतीयों की सभा को संबोधित करेंगे।

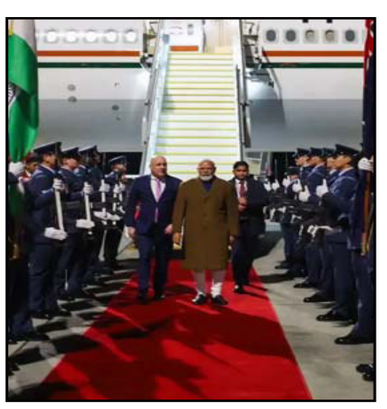

विकसित भारत की राह में जनसंख्या संतुलन का प्रश्न

ललित गर्ग
****

प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 की थीम है- ''युवाओं की उम्मीदों और आकांक्षाओं को साकार करना-आज और भविष्य के लिए।'' यह विषय स्पष्ट संकेत देता है कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य केवल उसकी जनसंख्या के आकार से नहीं, बल्कि उस जनसंख्या की गुणवत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और अवसरों से निर्धारित होता है। भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यह स्थिति एक ओर विशाल मानव संसाधन का अवसर प्रस्तुत करती है, तो दूसरी ओर संसाधनों, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और पर्यावरण पर अभूतपूर्व दबाव भी उत्पन्न करती है। इसलिए विश्व जनसंख्या दिवस भारत के लिए केवल औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि गंभीर आत्ममंथन का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक अवसरों पर छोटे परिवार के महत्व पर बल देते हुए कहा है कि जो परिवार स्वेच्छा से परिवार नियोजन अपनाते हैं, वे राष्ट्र-निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उनका यह संदेश बताता है कि जनसंख्या संतुलन किसी एक समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे देश के सतत विकास का विषय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न पदाधिकारियों ने भी समय-समय पर यह कहा है कि जनसंख्या नीति सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए तथा इसका उद्देश्य किसी समुदाय को लक्ष्य बनाना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित, संसाधनों के संतुलित उपयोग और सामाजिक समरसता को सुनिश्चित करना होना चाहिए। भारत आज वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। ''सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास'' का मंत्र तभी पूरी तरह साकार हो सकता है, जब विकास की गति और जनसंख्या वृद्धि के बीच संतुलन स्थापित हो। यदि जनसंख्या अनियंत्रित गति से बढ़ती रहे और संसाधनों का विस्तार उसी अनुपात में न हो, तो विकास की उपलब्धियां भी पर्याप्त सिद्ध नहीं होंगी। रोजगार के अवसर सीमित होंगे, कृषि योग्य भूमि सिकुड़ेगी, जल संकट गहराएगा, महानगरों पर दबाव बढ़ेगा और पर्यावरणीय असंतुलन गंभीर होता जाएगा। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या संबंधी विमर्श तथ्यों, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक सद्भाव पर आधारित हो। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देता है और जनसंख्या नीति का उद्देश्य भी समान रूप से सभी नागरिकों पर लागू होने वाला, न्यायसंगत एवं पारदर्शी ढांचा होना चाहिए। परिवार नियोजन, महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, विवाह की उपयुक्त आयु, आर्थिक सशक्तिकरण तथा जन-जागरूकता ऐसे उपाय हैं, जिनसे बिना किसी भेदभाव के जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में प्रभावी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। विश्व के अनेक अनुभव बताते हैं कि जैसे-जैसे शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा और आर्थिक विकास बढ़ता है, वैसे-वैसे प्रजनन दर स्वाभाविक रूप से घटती है। भारत के सामने एक अन्य गंभीर चुनौती अवैध घुसपैठ की भी है। सीमावर्ती क्षेत्रों में यदि अवैध रूप से लोगों का प्रवेश होता है और वे बिना वैधानिक प्रक्रिया के देश में बस जाते हैं, तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा, संसाधनों के वितरण तथा जनसांख्यिकीय संतुलन पर प्रभाव पड़ सकता है। यह विषय जनसंख्या नियंत्रण से अलग, कानून व्यवस्था और सीमा सुरक्षा का प्रश्न है। अतः सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना, अवैध प्रवासन पर प्रभावी नियंत्रण रखना तथा नागरिकता संबंधी कानूनों का निष्पक्ष पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। यह मुद्दा किसी धर्म या समुदाय के विरुद्ध नहीं, बल्कि कानून के शासन और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है। भारत को यह भी समझना होगा कि केवल कठोर कानून बना देना पर्याप्त नहीं होगा। चीन ने अपने समय में एक-संतान नीति अपनाई, लेकिन बाद में बदलती परिस्थितियों के कारण उसे वापस लेना पड़ा। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था चीन से भिन्न है। इसलिए भारत के लिए अधिक उपयुक्त मार्ग वह होगा जिसमें कानून के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता, स्वैच्छिक सहभागिता, शिक्षा और सकारात्मक प्रोत्साहन को प्राथमिकता दी जाए। छोटे परिवारों को प्रोत्साहन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान देना अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकता है। पिछले एक वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि विश्व की जनसंख्या लगभग 8.19 अरब से बढ़कर 8.30 अरब हो गई है, अर्थात एक वर्ष में लगभग 6.9 करोड़ लोगों की वृद्धि हुई है, जो लगभग 0.83 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाती है। दूसरी ओर भारत की जनसंख्या 1.45 अरब से बढ़कर लगभग 1.47 अरब हो गई है, यानी एक वर्ष में लगभग 1.25 करोड़ लोग और जुड़ गए। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 0.87-0.89 प्रतिशत के बीच है, जो वैश्विक औसत से थोड़ी अधिक है। भारत विश्व की कुल आबादी का लगभग 17.8 प्रतिशत हिस्सा रखता है। इतनी विशाल जनसंख्या के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, जल, ऊर्जा, कृषि भूमि और पर्यावरण पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। यदि जनसंख्या वृद्धि और विकास के बीच संतुलन स्थापित नहीं किया गया, तो विकसित भारत का लक्ष्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इसलिए केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है, बल्कि जनसंख्या स्थिरीकरण, मानव संसाधन विकास और संसाधनों के संतुलित नियोजन को भी समान प्राथमिकता देनी होगी। भारत में जनसंख्या का प्रश्न केवल सामाजिक या आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक विमर्श का भी विषय बन गया है। जातिगत जनगणना और विभिन्न जाति-समुदायों की जनसंख्या को लेकर राजनीतिक दल अक्सर अपने-अपने वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति अपनाते दिखाई देते हैं। अनेक विश्लेषकों का मानना है कि यदि जनसंख्या के आंकड़ों का उपयोग केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण या चुनावी लाभ के लिए किया जाएगा, तो यह राष्ट्रीय एकता और समावेशी विकास की भावना के विपरीत होगा। इसके विपरीत, चीन ने अपनी परिस्थितियों के अनुरूप लंबे समय तक कठोर जनसंख्या नियंत्रण नीति अपनाकर जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया, यद्यपि बाद में बदलती जनसांख्यिकीय चुनौतियों के कारण उसने उस नीति में संशोधन भी किया।

> **यह मुद्दा किसी धर्म या समुदाय के विरुद्ध नहीं, बल्कि कानून के शासन और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है। भारत को यह भी समझना होगा कि केवल कठोर कानून बना देना पर्याप्त नहीं होगा। चीन ने अपने समय में एक-संतान नीति अपनाई, लेकिन बाद में बदलती परिस्थितियों के कारण उसे वापस लेना पड़ा। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था चीन से भिन्न है। इसलिए भारत के लिए अधिक उपयुक्त मार्ग वह होगा जिसमें कानून के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता, स्वैच्छिक सहभागिता, शिक्षा और सकारात्मक प्रोत्साहन को प्राथमिकता दी जाए। छोटे परिवारों को प्रोत्साहन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान देना अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकता है।**

संम्पादकीय

जिम्मेदारी न लेने का घातक रोग

नोटबंदी, लॉकडाउन, चीन की घुसपैठ, पुलवामा और पहलगाम जैसे आतंकी हमले, मणिपुर में जनजातीय संघर्ष, बारिश, सूखा आदि की आपदाएं, पेपर लीक न जाने कितने मामलों में जनता को जान-माल हर तरह का नुकसान हुआ। अभी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कारण भावनात्मक तौर पर भी जनता बुरी तरह आहत है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी इन मामलों में आगे बढ़कर जिम्मेदारी नहीं ली या किसी गलत फैसले के लिए माफी नहीं मांगी, इस्तीफा देना तो दूर की बात है। वहीं आम जनता में से कोई जब किसी मामले पर सरकार की आलोचना करे तो उसे कैसे कानूनी शिकंजे में जकड़ा जाता है, इसकी बड़ी मिसाल उमर खालिद की गिरफ्तारी है। विपक्ष सरकार की आलोचना करे, तो नरेन्द्र मोदी उसे व्यक्तिगत निंदा मानकर कहते हैं कि गालियां उनके लिए टॉनिक का काम करती हैं। अब नरेन्द्र मोदी की राह पर ही देवेन्द्र फड़नवीस चल पड़े हैं। महाराष्ट्र में थोड़े दिनों की बारिश से हाहाकार मच चुका है। कई लोगों की जान चली गई है। 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाले और हाल ही में शुरू किए मुंबई-पुणे ‘मिसिंग लिंक’ एक्सप्रेसवे पर जो भूस्खलन हुआ और करीब 18 घंटे यातायात बंद रहा, तो विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए। साथ ही सोशल मीडिया पर भी सरकार की खिंचाई हुई। यह मुद्दा विधानसभा में भी उठा। विधानसभा में शहरों के विकास पर नियम 293 के तहत जब बहस हो रही थी तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने विपक्ष पर कड़ा हमला करते हुए इस परियोजना को इंजीनियरिंग का एक शानदार वैश्विक नमूना करार दिया। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फड़णवीस को बुरा-भला कहना ठीक है। मुझे इसकी आदत है। मुझ पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है, आज से 10 साल बाद, जो लोग आज बुरा-भला कह रहे हैं, वे शायद दिखाई न दें, लेकिन ‘कनेक्टिंग लिंक’ कायम रहेगा, और उस पर देवेंद्र फड़णवीस और एकनाथ शिंदे के नाम होंगे। आप मुझे जितना चाहें बदनाम करें, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र को बदनाम करेंगे, तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। इसके बाद अपनी भाषा का स्तर प्रचलित भाजपाई राजनीति के अनुरूप गिराते हुए फड़नवीस ने कहा कि जिनको कुत्ता भी नहीं पूछा, वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे भाड़े के टट्टू इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले-लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, ऐसे लोगों को कह देना चाहता हूं कि अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे तो छोड़ूंगा नहीं। देवेन्द्र फड़नवीस ने सदन की गरिमा को हाशिए पर धकलते हुए कुत्ते जैसे असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया और इस पर जिस तरह सदन में सत्ता पक्ष के लोगों ने उनका समर्थन किया, उससे जाहिर होता है कि सरकार को लोकतांत्रिक शालीनता और मर्यादा की कोई परवाह नहीं है। सोशल मीडिया पर पैसे लेकर ट्रोलिंग का काम भाजपा के शासन में ही खूब बढ़ा है और इसके पीछे किन लोगों का समर्थन रहा है, यह जनता जानती है। वैसे अगर संरचनात्मक गड़बड़ियों पर सरकार से ही जवाब मांगा जाएगा, इस पर भाजपा सरकार के लोग चिढ़ते क्यों हैं, यह समझ से परे है। हाल ही में एक वाकया उत्तरप्रदेश से सामने आया है, जब पत्रकार ने मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से सवाल किया कि मुख्यमंत्री के उद्घाटन से पहले ही लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे कई जगह से धंस गया है।

योगी के लिए विकास के रास्ते में अंधविश्वास की कोई जगह नहीं

सात्यकी चक्रवर्ती
****

उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक यह धारणा प्रचलित रही कि गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) जाने वाला मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी गंवा देता है। इसी वजह से कई पूर्व मुख्यमंत्री नोएडा जाने से बचते रहे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस राजनीतिक मिथक को न केवल चुनौती दी, बल्कि लगातार कई बार गौतमबुद्ध नगर का दौरा कर यह संदेश देने की कोशिश की कि विकास के रास्ते में अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। वर्ष 2017 से पहले कई मुख्यमंत्री गौतमबुद्ध नगर को शापित समझकर वहां नहीं जाते थे। उनको लगता था कि वहां जाने पर अगली सरकार उनकी नहीं बनेगी। वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने वहां जाकर इस मिथक को तोड़ा। वह वहां एक नहीं कई बार गए। उनका कहना है कि गौतमबुद्ध नगर शापित नहीं बल्कि देश का सर्वश्रेष्ठ निवेश गंतव्य बन रहा हैं। वर्षों की जकड़न टूटी है, कार्य संस्कृति बदली है और नागरिकों व उद्यमियों की समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने यहां के नोएडा व दादरी विधानसभा क्षेत्र में 2479 करोड़ से 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। 2017 से पहले मुख्यमंत्री यहां आने से बचते थे। बड़े आयोजनों में अपने मंत्रियों को भेज देते थे। 2012 से 2017 के बीच मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव व इससे पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती भी वहां नहीं गई। वर्ष 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेट्रो के उद्घाटन के लिए यहां आना था। प्रधानमंत्री कार्यालय से संदेश आया कि मुख्यमंत्री योगी यदि न आना चाहे तो किसी मंत्री को कार्यक्रम में भेज सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने तय किया कि वह स्वयं जाएंगे, किसी मंत्री को नहीं भेजेंगे। वह इन बातों को नहीं मानते। सरकार का काम जनता के लिए काम करना है। योगी के जाने के बाद अब यहां परिवर्तन दिख रहा है। घरेलू कमर्शियल उड़ानें शुरू हो चुकी हैं और जल्द ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। यहां लगभग 7000 करोड़ रुपये के निवेश से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट निर्माण की आधारशिला के साथ 8200 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की भी आधारशिला रखी गई है। इससे गौतमबुद्ध नगर इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। एक समय यह प्रदेश का सबसे खतरनाक क्षेत्र माना जाता था। लोग शाम के बाद यहां आने से डरते थे। आज वहीं फिल्म सिटी, अपैरल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क और बड़े-बड़े औद्योगिक निवेश हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि वह आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन रूढ़िवाद या अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते। उन्होंने यह भी कहा कि कभी इस जिले को ÷मनहूस÷ माना जाता था, लेकिन उन्होंने स्वयं वहां जाकर इस धारणा को तोड़ा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्षों तक यह चर्चा रही कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा जाता है, उसकी सत्ता दोबारा नहीं लौटती। इस धारणा के पीछे कुछ राजनीतिक घटनाएं थीं, जिनमें कई मुख्यमंत्रियों के नोएडा दौरे के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। हालांकि यह महज संयोग हैं, क्योंकि चुनावी जीत-हार का संबंध जनता के जनादेश, राजनीतिक परिस्थितियों और संगठनात्मक ताकत से होता है, किसी जिले के दौरे से नहीं। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने इस मिथक की परवाह किए बिना नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई दौरे किए। उन्होंने निवेश, औद्योगिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून-व्यवस्था से जुड़े कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लिया। जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, फिल्म सिटी और औद्योगिक परियोजनाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री कई बार गौतमबुद्ध नगर पहुंचे। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा दोबारा सत्ता में लौटी और योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इसे भी कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इस बात का प्रमाण माना कि नोएडा या गौतमबुद्ध नगर से जुड़ा तथाकथित ÷शाप÷ राजनीतिक वास्तविकता नहीं, बल्कि एक मिथक भर है। आज गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का इंजन माना जाता है। यहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल निर्माण में देश का प्रमुख केंद्र बन चुका है। डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और आईटी सेक्टर में बड़े निवेश हुए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास क्षेत्र में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यह संदेश देते रहे हैं कि सरकार का निर्णय अंधविश्वास नहीं बल्कि विकास की आवश्यकता तय करेगी। यही कारण है कि उन्होंने कई बार गौतमबुद्ध नगर जाकर करोड़ों रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया तथा प्रशासनिक बैठकों की अध्यक्षता भी की। गौतमबुद्ध नगर को मुख्यमंत्री के लिए ÷शापित÷ मानने वाली धारणा अब पहले जैसी राजनीतिक ताकत नहीं रखती। योगी आदित्यनाथ ने अपने लगातार दौरों, दोबारा मुख्यमंत्री बनने और जिले को प्रदेश के सबसे बड़े निवेश केंद्र के रूप में विकसित करने की रणनीति के जरिए इस मिथक को काफी हद तक अप्रासंगिक बना दिया है। आज गौतमबुद्ध नगर राजनीतिक अंधविश्वास की नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति, वैश्विक निवेश और आधुनिक बुनियादी ढांचे की पहचान बन चुका है।

आज का राशिफल

राशि	फल	राशि	फल
मेष	निकट संबंधों में शंकाओं को हावी न होने दें। भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति होने के आसार बनेंगे। नौकरी का वातावरण सुखद होगा। सगे-संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी।	मिथुन	संबंधों में कटु वचनों का प्रयोग न करें। माता के स्वास्थ के प्रति सचेत रहें। अच्छे कायरे द्वारा प्रशंसा के पात्र बनेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों को ग्रहों की अनुकूलता का लाभ मिलेगा।
वृषभ	आर्थिक क्षेत्र में लाभ के आसार हैं। अवरोधित कार्य हल होंगे। योजनाओं के फलीभूत होने से मन प्रसन्न होगा। विद्यार्थियों के लिए ग्रहों की अनुकूलता लाभप्रद होगी।	कर्क	बीती बातों को भूलने की कोशि करें। रोजगार में कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे। भौतिक इच्छाएं बलवती होंगी। अभिभावकों के भावनात्मक सहयोग से उत्साह में वृद्धि होगी।
सिंह	नकारात्मक चिंताओं का त्याग करें। महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अपनी पूर्ति हेतु मन पर दबाव बनाएंगी। वर्तमान में आपको सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक दिशा में प्रयास करना चाहिए।	तुला	महत्वाकांक्षाएं मन पर प्रभावी होंगी। घरेलू कायरें में अत्याधिक व्यय का योग है। कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी। परिवार में सुखद स्थिति प्रसन्नता लाएगी।
कन्या	किसी नये कार्य की ओर आपका रुझान बढ़ेगा। किसी महत्वपूर्ण फैसले के लिए मन केंद्रित होगा। नवीन योजनाओं द्वारा प्रगति होगी। जीवन साथी के साथ मधुरता कायम रखें।	वृश्चिक	परिश्रम का समुचित लाभ प्राप्त होगा। पारिवारिक वातावरण सुखद व उत्साहपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रयत्न तीव्र होगा।
धनु	मन सुंदर कल्पनाओं से प्रभावित रहेगा। नये संबंधों के प्रति निकटता बढ़ेगी। उपस्थित साधनों में सन्तुष्ट व तृप्त होने का प्रयत्न करें। जीवन साथी के स्वास्य के प्रति सतर्कता अपेक्षित है।	कुंभ	राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। अच्छे कायरे के लिए प्रशंसनीय होंगे। शासन-सत्ता से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन दुविधाग्रस्त होगा।
मकर	विभागीय परिवर्तनों से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अपने अन्दर धैर्य व वाणी में मधुरता लावें। कुछ नई अभिलाषाएं मन में जागृत होंगी। प्रियजनों का सनिध्य प्राप्त होगा।	मीन	आवेश में किये गये कार्य से कष्ट संभव। भावनात्मक समस्याओं पर सगे-संबंधियों के बीच खुलकर बात करें। कुछ नये उत्साह व कार्य क्षमता की अनुभूति करेंगे।

असहमति और विरोध का सिमटता दायरा और उम्मीद के स्वर

राजेश पांडेय
****

कानून और मर्यादा के दायरे में असहमति और विरोध जताने की आजादी स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। इसके माध्यम से लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। सरकार के सामने अपनी अपेक्षाएं रखते हैं। सरकार या अन्य प्रभावशाली तबकों की मनमानी के खिलाफभावनाओं का इजहार करते हैं। यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था की जरूरी शर्त है। इसलिए किसी को नुकसान पहुंचाए बिना विरोध व्यक्त करने के तरीकों को सभी वास्तविक लोकतांत्रिक देशों में संवैधानिक और सामाजिक मान्यता मिली है। लिहाजा, सवाल उठता है कि क्या संसद से लेकर गांवों तक अपने प्रतिनिधि चुनने वाले भारत में लोगों को सही अर्थों में अभिव्यक्ति की आजादी हासिल है या नहीं? क्या मीडिया और अन्य नागरिक संगठन अपनी मर्जी से काम करने के लिए स्वतंत्र है? बहरहाल,पूर्ण स्वतंत्रता जैसी आदर्श स्थिति तो कल्पना से परे है। अगर धरती पर कोई स्वर्ग होता तो शायद वहां भी पूरी आजादी नहीं मिल सकती थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में बोलने और लिखने की आजादी का प्रावधान है। असहमति और असंतोष समाज को दबावों से मुक्त करने के कारगर औजार हैं। लेकिन देश के कई राज्यों में बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने की प्रवृत्ति बढ़ी है। धरना, रैली के माध्यम से सरकार के फैसलों का विरोध करने वालों के खिलाफपुलिस कई बार सख्त कार्रवाई करती है। इसलिए बम्बई हाईकोर्ट के जस्टिस माधव जयाजीराव जामदार का यह कथन उम्मीद जगाता है कि क्या सभी नागरिक भारत सरकार के गुलाम हैं? जस्टिस जामदार ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता को नागरिकता कानून में संशोधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और नारे लगाने पर एक साल के लिए जिलाबदर करने के आदेश को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 में नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने और शान के साथ रहने का अधिकार है। लोगों को जनहित के मुद्दों पर अपनी आवाज उठाने का हक है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पुलिस अधिकारी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के सेवक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। जस्टिस जामदार की टिप्पणी ध्रुवीकरण और संवैधानिक संस्थाओं को महत्वहीन बनाने की कोशिश के दौर में बेहद अहम है। आम नागरिक की स्वतंत्रता का दायरा सिमट रहा है। उस पर लगातार संदेह और दबाव बढ़ा है। अभी हाल के कुछ फैसलों और मामलों पर नजर डालें तो लोगों को कदम-कदम पर परीक्षा देना पड़ रहा है। मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में वोटर पर अपनी पहचान साबित करने की पूरी जिम्मेदारी डाल दी गई है। तार्किक विसंगति जैसा अटपटा और अनोखा प्रावधान वोटर को मतदाता सूची में शामिल करने की बजाय बाहर करने से ज्यादा प्रेरित नजर आता है। पश्चिम बंगाल की एसआईआर का एक करिश्मा अभी हाल ही प्रकाश में आया है। कोलकाता के अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ के पूर्व संपादक आर राजगोपाल के पासपोर्ट का नवीनीकरण खटाई में पड़ गया। दरअसल, एसआईआर के दौरान उनका नाम मतदाता सूची से बाहर हो गया है। पासपोर्ट में देर के कारण वे अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अमेरिका नहीं जा पाए। अभी हाल में विदेश मंत्रालय ने यह कहकर लोगों की चिंता बढ़ा दी है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इससे नया विवाद खड़ा हो गया है। लोगों की पहचान से जुड़े कई दस्तावेज सरकार जारी करती है। फिर उन पर खुद सवाल उठाती है। एक अन्य फैसला नागरिक समाज पर सरकार की गहराती छाया की तस्वीर दिखाता है। विदेशी अंशदान विनियमन नियम (एफसीआरए) 2026 में संशोधन के जरिये विदेशी धन लेने वाले अशासकीय संगठनों (एनजीओ) को अपनी गतिविधियों को परिभाषित करना पड़ेगा, कामकाज का क्षेत्र बताना होगा और कई सूक्ष्म जानकारियां सरकार को देना होंगी। जाहिर है, ऐसे नियमों से अशासकीय संगठनों पर सरकार का शिकंजा मजबूत होगा। कुछ एनजीओ शिक्षा, स्वास्थ्य और कई अन्य क्षेत्रों में अच्छा मैदानी काम करते हैं। वे जरूरी मुद्दों पर जनमत जगाते हैं। नए नियम उनकी गतिविधियों पर असर डालेंगे। सरकार ने विदेशी धन के दुरुपयोग और गैरकानूनी धर्मपरिवर्तनों पर चिंता जताते हुए विदेशी सहायता लेने वाले एनजीओ पर नजर रखने के लिए कड़े नियम बनाए हैं। यहां अतीत की स्थिति पर नजर डालना भी उचित होगा। आम नागरिकों, मीडिया, गैर सरकारी संगठनों पर सरकार की पैनी नजर रखने के प्रावधान सिर्फबीते दस-बारह सालों में नहीं किए गए हैं। पहले भी सरकारें मीडिया और सिविल सोसायटी पर अंकुश लगाने के उपाय करती रही हैं। मिसाल के तौर पर देश में सबसे पहले सेंसरशिप इमरजेंसी के दौरान (1975-1977) लागू हुई थी। उस वक्त जानकारी के मुख्य स्रोत अखबार और सरकारी रेडियो, टेलीविजन (बहुत सीमित क्षेत्र में) थे। अखबारों के दफ्तरों में केंद्र सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो के अफसरों का आना-जाना रहता था। पीटीआई, यूएनआई, समाचार भारती और हिंदुस्तान समाचार को मिलाकर बनी सिर्फएक न्यूज एजेंसी ‘समाचार’ काम करती थी। सभी अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार एक स्रोत से आते थे। आपातकाल के दौरान सरकार की सख्ती के कारण अधिकतर अखबार सरकार की लाइन पर चलते थे। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की टिप्पणी गौरतलब है। इमरजेंसी के बाद उन्होंने कहा था, सरकार ने तो अखबारों से बैठने के लिए कहा था लेकिन वे तो उसके सामने जमीन पर लेट गए थे। 1976 में एफसीआरए कानून लागू किया गया था। उसमें 2010 में कुछ और सख्त प्रावधान किए गए। 2020 में सहयोगी संगठनों को विदेशी अंशदान ट्रांसफर करने पर रोक लगाई गई। इसका असर संगठनों के कामकाज पर पड़ा है। पिछले 12 वर्षों में मार्च 2026 तक लगभग बीस हजार संगठनों के एफसीआरए लायसेंस खत्म हो गए हैं। असहमति और विरोध को कुचलने का सुनियोजित दौर 2014 से ज्यादा तेज हुआ है। अलबत्ता 2024 के बाद उसमें थोड़ी गिरावट आई है।

चीन के जिनजियांग में जूता फैक्टरी में आग लगने से 28 की मौत

बीजिंग,। चीन के दक्षिण-पूर्वी फ़ुज़ियान प्रांत के जिनजियांग शहर स्थित एक जूते की फैक्टरी में भीषण आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई, जबकि 211 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे के वक्त फैक्टरी परिसर में कुल 239 कर्मचारी मौजूद थे।सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ और अन्य मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आग स्थानीय समयानुसार गुरुवार दोपहर जूता निर्माता कंपनी हुइटेंग की बहुमंजिला फैक्टरी में लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि कई कर्मचारी इमारत की छत पर फंस गए। सरकारी मीडिया द्वारा जारी वीडियो में इमारत से उठती ऊंची लपटें और आसमान में फैलता घना काला धुआं देखा गया।घटना के समय फैक्टरी में 239 कर्मचारी मौजूद थे। बचाव दल ने 213 लोगों को बाहर निकाल लिया, लेकिन इसमें से दो कर्मचारियों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई और लापता 26 अन्य कर्मचारियों के शव बाद में बरामद हुए।प्रारंभिक जांच के अनुसार आग फैक्टरी के निचले तल से शुरू हुई। जूता बनाने में इस्तेमाल होने वाली ज्वलनशील सामग्री और चिपकाने वाले रसायनों के कारण आग तेजी से पूरे भवन में फैल गई। वहीं, सीढ़ियों पर बड़ी मात्रा में रखा सामान बचाव और अग्निशमन कार्य में बाधा बना।स्थानीय अग्निशमन विभाग ने बताया कि कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया, हालांकि देर शाम तक घटनास्थल से धुआं उठता रहा और दमकल की गाड़ियां लगातार पानी का छिड़काव करती रहीं।

घटना के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खोज एवं बचाव अभियान में हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने दुर्घटना की विस्तृत जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। राष्ट्रपति ने कहा कि हाल के महीनों में कार्यस्थलों पर हुई कई गंभीर दुर्घटनाओं से सबक लेते हुए देशभर में औद्योगिक सुरक्षा उपायों को और सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।प्रधानमंत्री ली कियांग ने भी संबंधित विभागों को कार्यस्थलों पर सुरक्षा जोखिमों की व्यापक जांच करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।शिन्हुआ के अनुसार फैक्टरी के जिम्मेदार अधिकारियों और अन्य संबंधित कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही कंपनी के बैंक खाते भी फ्रीज़ कर दिए गए हैं। आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने घटनास्थल पर एक विशेष टीम भेजी है, जबकि फ़ुज़ियान प्रांतीय प्रशासन घायलों के इलाज और राहत कार्यों की निगरानी कर रहा है।

गौरतलब है कि जिनजियांग शहर चीन के सबसे बड़े जूता और परिधान निर्माण केंद्रों में शामिल है और इसे अक्सर देश की जूता राजधानी कहा जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यहां की हजारों कंपनियों ने वर्ष 2024 में 1.2 अरब से अधिक जोड़ी जूतों का उत्पादन किया, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 20 प्रतिशत है।

गाजा युद्धविराम के दूसरे चरण पर काहिरा में इजराइल, मिस्र और हमास की बैठकें

यरूशलेम/काहिरा। गाजा युद्धविराम समझौते के दूसरे चरण को आगे बढ़ाने के लिए इजराइल और मिस्र के सैन्य अधिकारियों के बीच काहिरा में अहम बातचीत हुई। इजराइल के सार्वजनिक प्रसारक की रिपोर्ट के अनुसार यह बैठक ऐसे समय में हुई जब हमास का एक प्रतिनिधिमंडल भी मिस्र की राजधानी में मध्यस्थों के साथ युद्धविराम समझौते के भविष्य पर चर्चा कर रहा है।तुर्किये की सरकारी संवाद समिति अनाडोलू की रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ इज़राइली सैन्य अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल पिछले दो दिनों से मिस्र के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ वार्ता में शामिल रहा। हालांकि, दोनों देशों ने बैठक में शामिल अधिकारियों की पहचान और बातचीत के नतीजों का खुलासा नहीं किया है।खलील अल-हय्या के नेतृत्व में हमास प्रतिनिधिमंडल युद्धविराम को मजबूत करने और समझौते के अगले चरण पर मध्यस्थों के साथ चर्चा के लिए काहिरा पहुंचा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये वार्ताएं गाज़ा समझौते के अगले चरण को आगे बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा हैं। वहीं, इज़राइल का दावा है कि हमास अब भी हथियार छोड़ने को तैयार नहीं है। गाज़ा युद्धविराम को लागू कराने और आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मिस्र, कतर और तुर्की मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि, मिस्र की ओर से इज़राइली मीडिया की रिपोर्ट पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

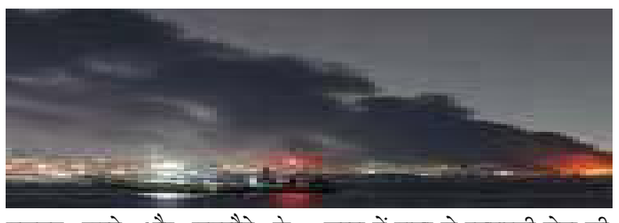

युद्धविराम समझौते के दूसरे चरण में गाज़ा से इज़राइली सेना की व्यापक वापसी, पुनर्निर्माण कार्यों की शुरुआत और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं पर सहमति बनने की परिकल्पना की गई है। हालांकि इजराइल का कहना है कि किसी भी अगले चरण से पहले फिलिस्तीनी सशस्त्र गुटों का निरस्त्रीकरण प्राथमिक शर्त होना चाहिए, जबकि हमास इस मांग का विरोध करता रहा है।गाज़ा में जारी संघर्ष के कारण मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है। युद्ध ने बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान पहुंचाया है और बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हुई है।

खैबर पख्तूनख्वा के करक में पुलिस मुठभेड़, चार संदिग्ध आतंकवादी मारे गए

इस्लामाबाद, । पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के करक जिले के खट्टक बांध इलाके में करक पुलिस, कोहाट पुलिस और सुरक्षा बलों के संयुक्त खुफिया अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ में चार संदिग्ध आतंकवादी मारे गए।

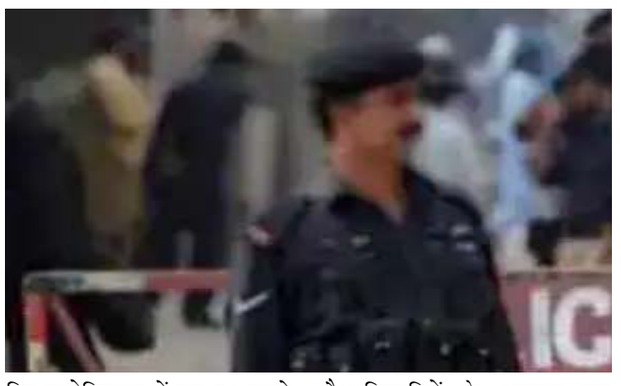

दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार खट्टक बांध इलाके में छुपे आतंकवादियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों को देखते ही गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में चार आतंकी मारे गए। इसके बाद सारे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह आतंकी पिछले दिनों मारे गए आतंकी कमांडर जाहिद के साथ रहते थे।अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सर्वाधिक आतंकवाद प्रभावित प्रांत हैं। पिछले दिन बलोचिस्तान में एन-25 हाइवे पर एक सैन्य अभियान के दौरान कम से कम 19 आतंकवादी मारे गए और 11 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। यह अभियान झाओ क्रॉस और करारो के बीच चलाया गया। यह आतंकवादी यहां जबरन वसूली करते थे। पाकिस्तान ने आतंकवाद से निपटने के लिए ऑपरेशन गजब लिल-हक शुरू किया है।अधिकारियों के अनुसार इस ऑपरेशन में अफगान तालिबान के कई सदस्य और सहयोगी आतंकी मारे जा चुके हैं। इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बल पूरी शिद्दत से आतंकवादियों का सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

स्पेन में जंगल की आग से 12 की मौत, 19 लापता

मैड्रिड । दक्षिणी स्पेन के अल्मेरिया प्रांत में लगी जंगल की आग में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग लापता हैं। कई पीड़ितों के शव जली हुई गाड़ियों के अंदर मिले हैं। देश में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और हीटवेव के बीच आग तेजी से फैली, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई।फ्रांस के समाचार टेलीविज़न नेटवर्क फ्रांस24 तथा तुर्किये की सरकारी संवाद समिति अनाडोलू ने क्षेत्रीय सरकार के हवाले से बताया कि अल्मेरिया प्रांत के बेदार और लॉस गैलार्डोस इलाके में फैली आग के बाद राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है। मृतकों की पहचान की प्रक्रिया चल रही है। अंडालूसिया के आपातकालीन मामलों के मंत्री एंटोनियो सैन्ज़ ने कहा कि शुरुआती संकेतों से लगता है कि मृतकों में अधिकांश, या संभवतः सभी, विदेशी नागरिक थे।इस हादसे में कम से कम आठ लोग घायल हुए हैं। इनमें एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति को धुएं के कारण सांस लेने में तकलीफ होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करीब 150 दमकलकर्मी और पांच दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटे हैं। आग उस समय भड़की जब इलाके का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बिजली की लाइन गिरने से सूखी वनस्पति में आग लगी, जो तेज हवाओं के कारण तेजी से आसपास के जंगल में फैल गई। हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक आग लगने के कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।आग के चलते कई सड़कों को बंद कर दिया गया और आसपास के इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लगभग 50 लोगों को अस्थायी रूप से एक सांस्कृतिक केंद्र में ठहराया गया है। स्पेन की मिलिट्री इमरजेंसी यूनिट (यूएमई) को भी राहत और बचाव कार्यों में शामिल किया जा रहा है।स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि जंगल की आग के भयावह परिणामों से वह बेहद व्यथित हैं। वहीं, अंडालूसिया के क्षेत्रीय प्रमुख जुआनमा मोरेनो ने इस घटना को एक बड़ी त्रासदी बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की।स्पेन इन दिनों भीषण हीटवेव की चपेट में है। अंडालूसिया के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने के कारण 'ऑरेंज वेदर वॉर्निंग' जारी की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बढ़ती गर्मी और सूखे हालात जंगल की आग की घटनाओं को और गंभीर बना रहे हैं।राष्ट्रीय मौसम एजेंसी एईएमईटी के अनुसार हाल के वर्षों में स्पेन में रिकॉर्ड स्तर की गर्मी दर्ज की गई है। इसी महीने की शुरुआत में भी कोस्टा ब्रावा क्षेत्र में लगी भीषण जंगल की आग के कारण हजारों लोगों को घरों में रहने के निर्देश दिए गए थे। वहीं, पिछले वर्ष देश में जंगल की आग से लगभग चार लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई थी, जो अब तक के सबसे बड़े प्रभावित क्षेत्रों में से एक है।

उत्तर कोरिया दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए बढ़ाएगा अपनी खुफिया

सियोल/प्योंगयांग । उत्तर कोरिया ने अपनी खुफिया और सैन्य निगरानी क्षमताओं को और मजबूत करने का फैसला किया है। शुक्रवार को सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी ऑफ़ कोरिया के केंद्रीय सैन्य आयोग की बैठक में जनरल रिकॉनिसेंस एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो (जीआरआईबी) के कामकाज और मिशन का दायरा बढ़ाने पर सहमति बनी। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सेना की युद्धक तैयारी, आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।

समाचार एजेंसी अनाडोलू तथा योनहाप न्यूज़ ने उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी के हवाले से बताया कि जीआरआईबी को संभावित दुश्मनों से जुड़े खतरों पर नजर रखने, अहम खुफिया जानकारी जुटाने और सैन्य टोही (रिकॉनिसेंस) क्षमताओं को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इन क्षमताओं का विस्तार किस तरह किया जाएगा।विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर कोरिया ने अपनी बाहरी खुफिया और विश्लेषण क्षमता को मजबूत करने के लिए पहले की जासूसी एजेंसी जनरल रिकॉनिसेंस ब्यूरो (जीआरबी) का विस्तार कर उसे जीआरआईबीके रूप में विकसित किया है।

गौरतलब है कि जीआरआईबी के अस्तित्व के बारे में पहली बार सितंबर (2025) में पता चला था। इसके प्रमुख री चांग-हो को इस साल 25 फरवरी को प्योंगयांग में हुई एक मिलिट्री परेड के दौरान विदेशी ऑपरेशन यूनिट्स का नेतृत्व करते हुए देखा गया था। यह परेड सत्ताधारी 'वर्कर्स पार्टी ऑफ़ कोरिया' के नौवें कांग्रेस (सम्मेलन) के मौके पर आयोजित की गई थी।दक्षिण कोरिया की क्यूंगनाम यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर फार ईस्टर्न स्टडीज़ के प्रोफेसर लिम यूल-चुल का कहना है कि बेहतर खुफिया नेटवर्क के जरिए उत्तर कोरिया गैर-सैन्य क्षेत्रों में भी अधिक सटीक अभियान चला सकता है। इनमें साइबर हमले, ड्रोन आधारित निगरानी और दक्षिण कोरिया के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटाना शामिल हो सकता है।बैठक में पीपुल्स आर्मी के वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति, तबादले और पदों से हटाने जैसे संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इससे सेना के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा सेना की राजनीतिक-वैचारिक मजबूती, सैन्य-तकनीकी क्षमता बढ़ाने और सभी स्तरों पर युद्धक तैयारी को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।बैठक में युद्ध प्रणालियों के तकनीकी ढांचे को आधुनिक बनाने, परमाणु शक्ति को गुणवत्ता और संख्या दोनों के लिहाज से मजबूत करने तथा सैन्य ठिकानों के आधुनिकीकरण की योजनाओं को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन ने बैठक के दौरान सात प्रमुख सैन्य आदेशों पर हस्ताक्षर भी किए।

किम जोंग ने कहा कि केवल इच्छाशक्ति से देश और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, जब हमारी सेना पर्याप्त मजबूत होगी और हर खतरे को नियंत्रित करने में सक्षम होगी, तभी वास्तविक शांति सुनिश्चित की जा सकेगी।बैठक में नौसेना के आधुनिकीकरण, कोयला खनन क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और अन्य राष्ट्रीय निर्माण परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई।

हमलों से दहला दक्षिणी ईरान, बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास शक्तिशाली विस्फोट

तेहरान/वाशिंगटन, । होर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी वर्चस्व की लड़ाई से खाड़ी देशों तक बारूदी सुरंग फैल चुकी है। भीषण संग्राम के बीच ईरान का बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र धमाकों से दहल उठा है। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान पर हुए ताजा हमलों में हाथ होने से इनकार किया है। इससे पहले 28 फरवरी को अमेरिका-इजराइल की एकीकृत सैन्य कार्रवाई के ठीक एक माह बाद 28 मार्च को ईरान के इस संयंत्र को निशाना बनाया जा चुका है।

ईरान का यह एकमात्र और पहला चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह फारस की खाड़ी के तट पर दक्षिणी ईरान के बुशहर शहर के पास स्थित है। हालिया संघर्ष के दौरान इसके आसपास के क्षेत्रों में मिसाइलें और प्रोजेक्टाइल गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। इसे 1970 के दशक में जर्मन कंपनियों ने बनाना शुरू किया था। बाद में इसे रूस के सहयोग से पूरा किया गया। यहां का पहला रिएक्टर (यूनिट-1) लगभग 1000 मेगावॉट बिजली राष्ट्रीय ग्रिड को प्रदान करता है। ताजा विस्फोट से व्यापक रेडियोधर्मी रिसाव का खतरा बढ़ गया है।अल जजीरा और एक्सिओस की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिणी ईरान के रणनीतिक इलाकों में एक के बाद एक कई जोरदार धमाकों ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। स्थानीय मीडिया और ईरानी अधिकारियों का दावा है कि बुशहर संयंत्र के बेहद नजदीकी सुरक्षा घेरे के साथ चोगादक सैन्य अड्डे और तटीय इलाकों को निशाना बनाया गया है। अब तक किसी ने भी इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। ना ही ईरान ने किसी पर आरोप मढ़ा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि वाशिंगटन हर हाल में ईरान के साथ बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है। तेहरान के साथ तकनीकी बातचीत जारी है।एक्सिओस की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका ने गुरुवार को हालात को शांत करने की कोशिश की। परमाणु समझौते तक पहुंचने के लिए तकनीकी स्तर की बातचीत जारी है। मध्यस्थों ने बुधवार को ईरान और अमेरिका के नेतृत्व से फोन पर बातचीत भी की। इस समय दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने पर सहमति बनाने और फिर तकनीकी टीमों के बीच बातचीत के अगले दौर के लिए तारीख तय करने के लिए बड़े पैमाने पर कूटनीतिक कोशिशें की जा रही हैं।अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व अमेरिकी मरीन कॉर्प्स अधिकारी डैन ग्रेजियर का कहना है कि इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ होने की पूरी संभावना है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थानीय समयानुसार गुरुवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी कदमों के बारे में जानकारी दी। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की एक्स पर साझा की गई पोस्ट में कहा गया, ''आज शाम दोनों नेताओं के बीच एक और बातचीत हुई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच लगातार तालमेल बनाए रखने पर सहमति बनी।''

दिल्ली - गवाही से पहले पत्नी की मौत

दिल्ली की एक अदालत ने 2021 के एक मामले में अपनी पत्नी की हत्या की कोशिश के आरोपी एक व्यक्ति को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित नहीं कर सका क्योंकि सुनवाई के दौरान गवाही देने से पहले ही शिकायतकर्ता की मौत हो गई थी। अभिनेश त्रिपाठी उर्फ राहुल के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय शर्मा ने 6 जुलाई के आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपना मामला साबित करने में विफल रहा। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता रश्मि ही एकमात्र मुख्य गवाह थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा इस मामले में, एकमात्र अहम गवाह यानी शिकायतकर्ता/पीड़िता रश्मि की मौत हो चुकी है और अभियोजन पक्ष ने किसी ऐसे दूसरे गवाह का ज़िक्र नहीं किया है, जो आरोपी द्वारा की गई किसी प्रत्यक्ष हरकत के बारे में गवाही दे सके।अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला अप्रैल 2021 में रश्मि द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से शुरू हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने आरोपी के कहने पर एक अनजान व्यक्ति से बात करने से इनकार कर दिया, तो उनके पति ने उनके साथ मारपीट की। शुरुआत में उन्होंने कहा कि पति ने हॉकी स्टिक से उन्हें पीटा और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद त्रिपाठी के खिलाफ ढ्ढक्कष्ट की धाराओं 307, 323, 341 और 506 के तहत स्नढ्ढक्रदर्ज की गई। अस्पताल में इलाज के दौरान, रश्मि ने एक अतिरिक्त बयान दिया जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी नशे की हालत में घर लौटा और जान से मारने की धमकी देते हुए उसे घर की तीसरी मंज़िल से नीचे फेंक दिया। इसके बाद, हत्या के प्रयास का आरोप भी जोड़ा गया।ट्रायल के दौरान, रश्मि को भेजे गए समन बिना तामील हुए वापस आ गए क्योंकि वह अपना किराए का घर छोड़कर चली गई थी। बाद में उसके पिता ने कोर्ट को बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि मरने से पहले उसने आरोपी के साथ सभी विवाद सुलझा लिए थे, आपसी सहमति से तलाक ले लिया था और 8 लाख रुपये का गुजारा-भत्ता (एलिमनी) भी ले लिया था। कोर्ट ने कहा कि रश्मि का बयान दर्ज नहीं किया जा सका और अभियोजन पक्ष के बाकी गवाह सिर्फ़ औपचारिक पुलिस गवाह थे। कोर्ट ने माना कि अगर उनके सबूतों को मान भी लिया जाए, तो भी वे आरोपों को साबित करने के लिए काफ़ी नहीं थे। यह देखते हुए कि जिस शिकायत के आधार पर केस चल रहा था, वह साबित नहीं हो पाई और आरोपी को अपराधों से जोड़ने वाला कोई ठोस सबूत नहीं मिला, कोर्ट ने त्रिपाठी को बरी कर दिया।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बड़ी कामयाबी, अब तक खुले 93.95 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य खाते

देश में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप देने की मुहिम तेजी से आगे बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक बनकर उभरा है। इस मिशन के तहत अब तक 93.95 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत खाते खोले जा चुके हैं। इसके साथ ही, लगभग 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स को भी इस प्रणाली से जोड़ा जा चुका है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य रजिस्ट्री में अब तक 5.33 लाख स्वास्थ्य केंद्रों और 9.85 लाख स्वास्थ्य पेशेवरों का पंजीकरण किया जा चुका है।मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस डिजिटल पहल के तहत देश के 2.72 लाख स्वास्थ्य केंद्रों ने एबीडीएम-सक्षम सॉफ्टवेयर को अपनाया है। इसकी मदद से अस्पतालों में ओपीडी पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद आसान और तेज हो गई है। तेजी से ओपीडी पंजीकरण के लिए अब तक लगभग 24 करोड़ 'स्कैन और रजिस्टर' टोकन जारी किए जा चुके हैं। इस प्रणाली से स्वास्थ्य क्षेत्र में मरीजों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों का उनकी सहमति से सुरक्षित और सुगम आदान-प्रदान संभव हो सका है।इस प्रगति की समीक्षा हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा की अध्यक्षता में आयोजित 'मिशन स्टीयरिंग ग्रुप' की तीसरी बैठक में की गई। इस बैठक में देश के डिजिटल स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करने की भविष्य की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा कि डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा नागरिकों को उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक सुरक्षित और सहमति-आधारित पहुंच प्रदान कर उन्हें सशक्त बना रहा है।स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तकनीक को एक प्रभावी माध्यम के रूप में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि हर नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवाएं समावेशी, सुलभ और उपयोग में आसान हों। बैठक के दौरान मिशन स्टीयरिंग ग्रुप ने पिछली बैठक के निर्णयों की प्रगति भी आंकी, जिसमें राज्यों में इसे लागू करने के तरीकों को मजबूत करना, सरकारी योजनाओं में डिजिटल स्वास्थ्य मंच को जोड़ना और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की भागीदारी बढ़ाना शामिल था।

50 करोड़ की स्कॉलरशिप से 3,000 प्रतिभाओं को मिला करियर का मंच

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है। इसी कड़ी में देश की पहली एआई ऑगमेंटेड मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में दो दिवसीय 'सीयू स्कॉलर समिट 2026' के फेज 2 का रविवार को भव्य शुभारंभ हुआ। समिट के पहले दिन बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 750 से अधिक मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव

अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में शिक्षा और कौशल विकास को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 3,000 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को लगभग 50 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति देकर नया आयाम स्थापित किया है। यह साबित करता है कि योगी सरकार की नीतियों में आर्थिक संसाधनों की कमी किसी भी प्रतिभा की शिक्षा में बाधा नहीं बनेगी।

उन्होंने कहा कि आज प्रतिस्पर्धा के दौर में युवाओं को एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, एयरोस्पेस और डिफेंस जैसी उभरती तकनीकों में दक्ष होना होगा। 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के विजन को योगी सरकार धरातल पर उतार रही है। हमारा लक्ष्य है कि यूपी का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने।' उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेटियों को भी उच्च शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में बराबरी के अवसर मिल रहे हैं।सीयू यूपी के मैनेजिंग डायरेक्टर जय इंदर सिंह संधू ने कहा कि एक वर्ष पहले हमने स्पष्ट विजन के साथ सीयू यूपी की नींव रखी थी। आज हमारे कैंपस में एडवांस लैब्स, जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई स्पेस और विश्वस्तरीय रिसर्च सुविधाएं हैं। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री-ड्रिवन लर्निंग मॉडल के कारण कई छात्र पहले ही ग्लोबल कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए चयनित हो चुके हैं। एआई हर क्षेत्र बदल रहा है। सीयू यूपी देश का पहला एआई स्पेस विकसित कर छात्रों को भविष्य के लिए तैयार कर रही है।

यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सीयूसीईटी के माध्यम से 50 करोड़ रुपये तक की स्कॉलरशिप की घोषणा की थी। मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों को 100 प्रतिशत तक की स्कॉलरशिप मिली है। पहले दिन इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग के 750 से अधिक विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।

'फ्रॉम स्कॉलर टू फ्यूचर-रेडी प्रोफेशनलः एआई, एयरोस्पेस, डिफेंस एंड इंजीनियरिंग' थीम पर हुए सत्रों में पॉलिसी मेकर्स, एजुकेशनिस्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और एलुमनाई ने फ्यूचर स्किल्स पर मंथन किया।

संक्षिप्त समाचार

एयरफोर्स तिराहे के पास सड़क हादसे में महिला की मौत, तीन घायल

लखनऊ, । राजधानी के बीकेटी थाना क्षेत्र में एयरफोर्स तिराहे के निकट बुधवार देर रात हुए सड़क हादसे में 22 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल कार को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है।पुलिस के अनुसार, 8 जुलाई की रात करीब 10:40 बजे एयरफोर्स तिराहे के पास सड़क दुर्घटना की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (यूपी34बीवाई6980) पर सवार 17 वर्षीय अमन कुमार गौतम, अरुण कश्यप की 22 वर्षीय पत्नी, उनका पांच माह का पुत्र तथा अमन की बहन सीतापुर से लखनऊ लौट रहे थे। इसी दौरान कट से मुड़ रही ऑल्टो कार (यूपी32आरएच2428) ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल राम सागर मिश्र 100 शैय्या चिकित्सालय, साढ़ामऊ पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने 22 वर्षीय महिला को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों का उपचार जारी है।पुलिस ने दुर्घटना में शामिल ऑल्टो कार को कब्जे में ले लिया है। कार चालक लक्ष्य मिश्रा (30 वर्ष) को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।पुलिस ने मृतका के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर नियमानुसार मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था सामान्य बनी हुई है।

मथुरा में फर्जी पत्रकार बनकर वसूली का आरोप खबर रोकने के नाम पर ?10 हजार मांगने का दावा CCTV में कैद पूरी घटना

मथुरा ब्यूरो चीफ

अगर कोई आपके घर आए... खुद को पत्रकार बताए... लेकिन पहचान पत्र न दिखाए... और फिर खबर रोकने के नाम पर पैसों की मांग करे... तो क्या वह पत्रकार है या ब्लैकमेलर? मथुरा से एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने दो लोगों पर फर्जी मीडिया कर्मी बनकर घर पहुंचने और कथित रूप से 10 हजार रुपये की मांग करने का आरोप लगाया है। मथुरा में फर्जी मीडिया कर्मी बनकर कथित वसूली करने का एक मामला सामने आया है। एक महिला ने पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि दो लोग, जिनमें एक पुरुष और एक महिला शामिल थे, उनके घर पहुंचे और स्वयं को मीडिया कर्मी बताया। शिकायत के अनुसार, जब महिला ने दोनों से उनका मीडिया पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा, तो वे कोई वैध पहचान पत्र नहीं दिखा सके। इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर कहा कि उन्हें सुनील चौधरी ने भेजा है और महिला के पति से जुड़े एक मुकदमे की खबर प्रकाशित या प्रसारित की जाएगी। महिला का आरोप है कि दोनों व्यक्तियों ने कहा कि यदि वह यह खबर नहीं चलवाना चाहती हैं तो उन्हें 10 हजार रुपये देने होंगे। शिकायत के अनुसार, उनसे यह भी कहा गया कि ₹फैसला आपके हाथ में है। महिला ने उन्हें बताया कि संबंधित मुकदमे की जांच फिलहाल क्राइम ब्रांच, मथुरा कर रही है। इसके बाद जब उन्होंने पुलिस बुलाने की बात कही, तो शिकायत के अनुसार दोनों व्यक्ति वहां से भाग गए। महिला का कहना है कि पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है। उन्होंने पुलिस से आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। इस घटना के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि पत्रकारिता की आड़ में आम लोगों को डराने और कथित रूप से धन उगाही करने की कोशिश करने वाले ऐसे लोगों पर कब तक कार्रवाई होगी? क्योंकि ऐसे मामलों से वास्तविक पत्रकारों की छवि भी प्रभावित होती है। फिलहाल यह सभी आरोप शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए हैं। पुलिस की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं, तो यह मामला केवल कथित वसूली का नहीं, बल्कि पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है। अब देखना होगा कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। यदि आपके साथ भी इस तरह के लोगों ने मीडिया या किसी सरकारी विभाग का नाम लेकर पैसे मांगने या दबाव बनाने की कोशिश की है, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुलहवार्ता विफल

न्यायालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आदेश किया पारित, दो बार बुलाने पर भी नहीं पहुंचा मुस्लिम पक्ष, अब पत्रावली जा सकती है सुप्रीम कोर्ट

मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण में समझौते की संभावनाओं को तलाशने के लिए आयोजित सुलहवार्ता विफल हो गई है। न्यायालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इस संबंध में गुरुवार को आदेश पारित कर दिया गया। मुस्लिम पक्ष को समझौते के लिए दो बार अवसर दिए जाने के बावजूद वह सुलहवार्ता में उपस्थित नहीं हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर मथुरा में विशेष लोक अदालत (सुलहवार्ता) का आयोजन किया गया था। इसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण से संबंधित विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) में आपसी सहमति से समाधान की संभावना तलाशने का प्रयास किया गया। सुलहवार्ता की अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-11) सुरेंद्र प्रसाद ने की। निर्णय के दौरान सचिव और सदस्य भी मौजूद रहे। श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद केस के हिंदू पक्षकार एवं अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने बताया कि न्यायालय की ओर से मुस्लिम पक्ष को समझौते की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए दो बार बुलाया गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद न्यायालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सुलहवार्ता की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आदेश पारित कर दिया। महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हिंदू पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा गया। उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष का प्रस्ताव था कि यदि मुस्लिम पक्ष विवादित स्थल से अपना दावा छोड़कर ढांचा हटाने को तैयार होता है तो अन्य स्थान पर मस्जिद निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष विवादित स्थल को भगवान श्रीकृष्ण का प्राकट्य स्थल मानता है और इसी आधार पर न्यायालय के समक्ष अपने तथ्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। उन्होंने बताया कि अब सुलहवार्ता से संबंधित पत्रावली सर्वोच्च न्यायालय भेजी जा सकती है।

मथुरा में 26वें राष्ट्रीय कृषक दिवस का आयोजन

मथुरा ब्यूरो

मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, दुवासु, मथुरा में 26वें राष्ट्रीय कृषक दिवस का आयोजन आज दो चरणों में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य मत्स्य पालन को बढ़ावा देना तथा किसानों को आधुनिक तकनीकों से अवगत कराना था। कार्यक्रम के प्रथम चरण में भारतीय मेजर कार्प प्रजातियों की लगभग 15,000 अंगुलिकाओं का यमुना नदी में संचयन (रैंचिंग) किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शैल्जाकान्त मिश्रा, उपाध्यक्ष, ब्रज तीर्थ विकास परिषद माननीय कुलपति डॉ. अभिजीत मित्रा, दुवासु जिला वन अधिकारी, अपर जिला मजिस्ट्रेट, सहायक निदेशक मत्स्य विभाग तथा अधिष्ठाता मत्स्य विज्ञान सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यमुना नदी में जैव विविधता को बढ़ावा देना तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना था। द्वितीय चरण के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय कुलपति महोदय एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. सुभादीप घोष, सहायक महानिदेशक (मत्स्य), आईसीएआर तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में हाथरस, अलीगढ़ एवं मथुरा जनपदों के लगभग 120 किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर देश की प्रतिष्ठित फीड एवं मेडिसिन कंपनियों द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों, पोषण एवं रोग प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। अपने संबोधन में माननीय कुलपति डॉ. अभिजीत मित्रा ने आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर मत्स्य उत्पादन बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने किसानों को मोती पालन, झींगा पालन तथा रंगीन मछली पालन जैसे उभरते क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। डॉ. सुभादीप घोष ने अपने संबोधन में मत्स्य क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने किसानों को वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने, गुणवत्तापूर्ण बीज एवं संतुलित आहार के उपयोग तथा रोग प्रबंधन के प्रति सजग रहने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने मत्स्य पालन को आयवृद्धि का सशक्त माध्यम बताते हुए इसे स्वरोजगार एवं उद्यमिता के रूप में विकसित करने पर बल दिया। कार्यक्रम के दौरान 5 प्रगतिशील किसानों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया।

पशुपालन विभाग राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आज

लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा पशु चिकित्सकों के लिए जूनोटिक (पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाले) एवं प्राथमिक पशु रोगों पर दिनांक 09 व 10 जुलाई को दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का होटल गोल्डन ट्यूलिप, लखनऊ में पूर्वाहन 10:00 बजे से किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण को झपाइगो का तकनीकी सहयोग प्राप्त है तथा इसमें प्रदेश भर के वरिष्ठ अधिकारी, विषय विशेषज्ञ और पशु चिकित्सक प्रशिक्षण ले रहे हैं।पशुपालन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यक्रम का उद्घाटन श्री मुकेश कुमार मेश्राम, अपर मुख्य सचिव, पशुपालन विभाग, श्री देवेंद्र कुमार पाण्डेय, विशेष सचिव, पशुपालन विभाग, डॉ. संगीता तिवारी, निदेशक, पशुपालन विभाग, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, निदेशक (प्रशासन एवं विकास) सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया जाएगा।इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकारी पशु चिकित्सकों की तकनीकी एवं प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाना है, ताकि वे जूनोटिक एवं प्राथमिक पशु रोगों की शीघ्र पहचान, प्रारंभिक निदान, निगरानी, रिपोर्टिंग, रोकथाम और नियंत्रण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकें।इसके साथ ही, इस कार्यक्रम के माध्यम से मास्टर ट्रेनर्स का एक समूह तैयार किया जाएगा, जो आगे चलकर जिला एवं क्षेत्रीय स्तर पर पशु चिकित्सकों और पैरावेटरिनरी कर्मियों को प्रशिक्षित करेंगे। इससे राज्य में रोग निगरानी एवं महामारी की तैयारी को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।दो दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को रेबीज, अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा , लेप्टोस्पायरोसिस, जापानी इंसेफेलाइटिस, बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस, क्राइमियन-कांगो हेमोरेजिक फीवर , एन्थ्रेक्स, स्क्रब टायफस, ग्लैंडर्स, लम्पी स्किन डिजीज, ब्रूसेलोसिस, साल्मोनेलोसिस, डर्माटोफाइटोसिस जैसे महत्वपूर्ण रोगों पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी।प्रशिक्षण में रोगों के प्रसार, संक्रमण के तरीके, प्रमुख लक्षण, संदिग्ध एवं पुष्ट मामलों की पहचान, रोकथाम एवं नियंत्रण उपाय, निगरानी एवं रिपोर्टिंग प्रणाली, प्रयोगशाला जांच क्षमता, जैव सुरक्षा तथा नमूनों के सही संग्रह, पैकेजिंग एवं

राजनाथ सिंह के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर 50 ट्राफिक पुलिस कर्मियों को दिया गया छाता

लखनऊः अखिल भारतीय ब्रह्म समाज द्वारा रक्षामंत्री भारत सरकार एवं सांसद लखनऊ राजनाथ सिंह जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर संगठन के महामंत्री देवेन्द्र शुक्ल के आह्वान पर आलमबाग चौराहे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 50 ट्राफिक पुलिस कर्मियों को छाता वितरण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर के अध्यक्ष आनन्द द्विवेदी जी ने कहा कि ब्रह्म समाज सदैव अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में अग्रणी भूमिका निभाता है! उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में सामाजिक समरसता का भाव जगृत होता है! उन्होंने भव्य आयोजन के लिए संगठन के अध्यक्ष सी पी अवस्थी एवं महामंत्री देवेन्द्र शुक्ल जी का आभार प्रकट किया! संगठन के अध्यक्ष सी पी अवस्थी जी ने कहा कि ट्राफिक पुलिस कर्मी भीषण गर्मी, बरसात में अपनी चिंता न करते हुए समाज को सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहते हैं और राष्ट्र सेवा में अपना अमूल्य योगदान देते हैं! संगठन ऐसे राष्ट्र भक्त सिपाहियों को सम्मानित करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है! संगठन के महामंत्री देवेन्द्र शुक्ल ने इस कार्यक्रम को अपने ब्रह्मलीन पिता श्री करुणा शंकर शुक्ल जी को समर्पित करते हुए कहा कि उनके द्वारा जो समाज के सभी लोगों के प्रति सेवा का संस्कार दिया गया यह उसी की परिणिति है! भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश किसान उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजय त्रिपाठी मुन्ना ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए आयोजकों को ऐसे आयोजन के लिए बधाई देते हुए रक्षामंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करते हुए सुन्दर व्यवस्था के लिए रामरूप पप्पू यादव और अभिषेक शुक्ल का हृदय से आभार व्यक्त किया! कार्यक्रम की सम्पूर्ण व्यवस्था आलमबाग लखनऊ व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष राम रुप पप्पू

यादव और युवा कार्यकर्ता अभिषेक शुक्ल ने की! संचालन संगठन के प्रदेश महासचिव कौशिक बनर्जी ने किया! इस अवसर पर संस्था के संस्थापक सदस्य श्री सुधांशु शुक्ल, गिरिजा शंकर त्रिपाठी, श्री प्रदीप पाण्डेय, राजीव शुक्ल, श्री विजय मिश्र, राकेश श्रीवास्तव, शेष नारायण पाण्डेय, अंजनी कुमार दीक्षित, विकास मिश्र, चन्द्र प्रकाश मिश्र, राम किशोर मिश्र, एस के तिवारी, श्रीमती प्रभा मिश्रा, बबुशा शुक्ल, रागिनी दुबे, रीतू तिवारी, सुमन, श्रीमती वन्दना तिवारी, सुमित मिश्र, कृष्ण दत्त अवस्थी आलमबाग लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजय सन्मुख, पवित्र सिंह, श्री राजकुमार आदि बहुत से पदाधिकारी उपस्थित हुए।

अमृत सरोवर निर्माण में यूपी देश में शीर्ष पर, 19989 सरोवरों का किया गया निर्माण

लखनऊ, । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जल संरक्षण और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना व अमृत सरोवर योजना 2.0 के तहत प्रदेश में 19,989 अमृत सरोवरों का निर्माण और पुनरुद्धार किया जा चुका है। ग्राम्य विकास विभाग के अनुसार अमृत सरोवरों के निर्माण और पुनरुद्धार के मामले में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। इस अभियान से जल संरक्षण को मजबूती मिलने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। अमृत सरोवर निर्माण अभियान में प्रदेश पांच जिले हरदोई, आजमगढ़ गोरखपुर, महराजगंज व प्रयागराज टॉप पांच में शामिल हैं। यहां हरदोई प्रदेश में पहले स्थान पर है, जहां 1,202 सरोवरों का निर्माण किया जा चुका है। इसके अलावा आजमगढ़ में 797, गोरखपुर में 734, महराजगंज में 726 और प्रयागराज में 638 अमृत सरोवर विकसित किए गए हैं। प्रदेशभर में अब तक निर्माण एवं पुनरुद्धार का कूल आंकड़ा 19,989 तक पहुंच चुका है। अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य केवल पुराने जल स्रोतों

का संरक्षण करना नहीं है, बल्कि वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देकर भूजल स्तर में सुधार लाना भी है।

इन सरोवरों के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए अतिरिक्त जल उपलब्ध हो रहा है, जिससे कृषि गतिविधियों को मजबूती मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ने के साथ पर्यावरणीय संतुलन को भी बल मिला है।

योगी सरकार ने अमृत सरोवरों को केवल जल संचय तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें ग्रामीण जीवन का आकर्षक केंद्र भी बनाया है। प्रत्येक अमृत सरोवर को कम से कम एक एकड़ क्षेत्रफल में विकसित किया गया है, जिसकी जल क्षमता लगभग 10 हजार घन मीटर है। सरोवरों के चारों ओर पक्के पैदल मार्ग, बैठने के लिए बेंच, प्रकाश व्यवस्था और व्यापक वृक्षारोपण की व्यवस्था की गई है। इससे गांवों में हरियाली और स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा मिला है। अमृत सरोवर योजना का एक बड़ा लाभ ग्रामीण रोजगार के रूप में भी सामने आया है। सरोवरों की खुदाई, गाद निकालने और सुंदरीकरण के कार्यों को वीबी जी राम जी (पूर्व में मनरेगा) से जोड़ा गया है। इससे प्रदेश के लाखों ग्रामीण परिवारों को अपने ही गांव में रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर आय के नए स्रोत भी विकसित हुए हैं। अमृत सरोवरों के निर्माण और पुनरुद्धार से जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास के लक्ष्यों को एक साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण हरियाली बढ़ाने और कृषि को सहयोग देने के साथ यह योजना गांवों में सतत विकास की मजबूत नींव तैयार कर रही है। ग्राम्य विकास विभाग के अनुसार अमृत सरोवर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण उत्तर प्रदेश देश के अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में उभरकर सामने आया है।

यूपीईएसएससी ने प्रवक्ता भर्ती-2022 का अंतिम परिणाम घोषित, 18 विषयों के 624 पदों पर चयन

लखनऊ : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज ने सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता (बालक/बालिका) भर्ती-2022 का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि विज्ञापन संख्या-02/2022 के अंतर्गत 18 विषयों के कुल 624 प्रवक्ता पदों के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है।अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सरकारी सेवा में अवसर उपलब्ध कराना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी क्रम में प्रवक्ता भर्ती-2022 की पूरी प्रक्रिया निष्पक्षता और शुचिता के साथ संपन्न कराई गई। उन्होंने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रवक्ता भर्ती की लिखित परीक्षा 09 एवं 10 मई 2026 को आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 15 जून से 27 जून 2026 तक संपन्न कराया गया। लिखित परीक्षा, अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार की समस्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग ने अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है।उन्होंने बताया कि भौतिकी, जीवविज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास, शिक्षा, अंग्रेजी, कृषि, वाणिज्य, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी तथा कला सहित कुल 18 विषयों के चयनित अभ्यर्थियों का विषयवार एवं श्रेणीवार विवरण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। अभ्यर्थी कटऑफ अंक एवं चयन संबंधी विस्तृत जानकारी भी वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं।

अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक एवं जन्मतिथि के माध्यम से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से एक सप्ताह तक अपने प्राप्तांक देख सकेंगे। इसके अतिरिक्त प्राप्तांकों से संबंधित कोई भी सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली, 1998 के नियम 12(9) के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करते समय ऑनलाइन भरी गई संस्थाओं की अधिमानता तथा घोषित चयन पैनल के आधार पर नियम 12(10) के प्रावधानों के अनुरूप संस्था आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी।

साइबर युग में अपराध के तरीके बदल रहे हैं,रहना होगा सावधान: डॉ जी के गोस्वामी

लखनऊः उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ़ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ में आज रक्षा लेखा विभाग, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (ऋष्ठ कैंट लखनऊ) में प्रशिक्षणरत रक्षा लेखा विभाग के 40 अधिकारियों ने परिभ्रमण किया। जिन्हें संस्थान के विषय विशेषज्ञों द्वारा साइबर एवं फोरेंसिक विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। इस अवसर पर संस्थापक निदेशक डॉ जी0के0 गोस्वामी ने सभागार में उपस्थित समस्त अधिकारियो को संबोधित करते हुए कहा कि साइबर युग में अपराध के तरीके बदल रहे हैं इसलिए हमें सावधान रहना होगा7 पहले फिजीकल दुनियां में अपराध होते थे लेकिन अब डिजीटल दुनियां में अपराध हो रहे है ऐसे में तकनीक के बारे मे हम सभी को अधिक से अधिक जानकारी रखनी होगी और उसी के अनुसार कार्य करना होगा अन्यथा साइबर ठगी के शिकार हो सकते हैं 7 उन्होंने डेटा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिसके पास जितना डेटा होगा वह उतना ही मजबूत होगा, कुछ देश इसलिए शक्तिशाली हैं क्योंकि वह अपनी तकनीक और

डाटा अन्य देशो से शेयर नहीं करते । उन्होंने कहा कि अभी आप लोगों का प्रशिक्षण का काल है जितना जिज्ञासु होगें उतना ही नई-नई चीजों को सीख पायेगें । यह संस्थान वर्तमान में साइबर सुरक्षा तथा फोरेंसिक विषय में विभिन्न संस्थानों को तकनीकी दक्षता आज निपुण कर रहा है ।इस अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक श्री हेमराज मीना ने प्रशिक्षु अधिकारियो को संस्थान के बारे में ब्रीफ किया तथा आज के युग में साइबर फोरेंसिक क्यों महत्वपूर्ण है? इस विषय पर प्रकाश डाला । कार्यक्रम के अंत में उप निदेशक जितेन्द्र श्रीवास्तव ने सभागार में उपस्थित समस्त अधिकारियों का अभार प्रकट किया । कार्यक्रम का संचालन जनसंपर्क अधिकारी संतोष तिवारी ने तथा डॉ इंद्रजीत ने साइबर विषय पर व्याख्यान दिया। प्रशिक्षु अधिकारियो ने डीएनए तथा एआई लैब का भी विजिट किया। इस अवसर पर, उप निदेशक चिरंजीब मुखर्जी, अतुल यादव, डॉ0 आनंद प्रकाश, अमित मिश्र, राहुल दिवेदी, डॉ पलक, आरआई शैलेन्द्र सिंह एवं कार्तिकेय सहित अन्य उपस्थित रहे।

नाम संशोधन संबंधी सार्वजनिक सूचना

मैं, किशन गौतम, यह घोषित करता हूँ कि मेरे पुत्र का नाम विद्यालय के अभिलेखों में त्रुटिवश अक्षित कश्यप दर्ज हो गया था, जबकि उसका सही नाम अक्षित सिंह है। अतः भविष्य में सभी शैक्षणिक, सरकारी एवं अन्य अभिलेखों में उसके सही नाम अक्षित सिंह को ही पढ़ा एवं दर्ज किया जाए।

स्थानः गोरखपुर
दिनांकः 27/06/2026
(किशन गौतम)
अभिभावक

डॉ. शक्ति सिंह साधू (प्रधान सम्पादक), डॉ. प्रवीण (प्रबंध सम्पादक), एडवोकेट शैलेन्द्र श्रीवास्तव (कानूनी सलाहकार), राकेश अग्रवाल (जिला ब्यूरो उत्तर प्रदेश) अब्दुल नासिर स्टेट ब्यूरो उत्तर प्रदेश

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक शक्ति सिंह द्वारा राज तरूण आफसेट, एल0जी0एफ0 5–14, अंसल सिटी सेंटर, हजरतगंज, लखनऊ– 226001 से मुद्रित तथा 486/238–डी, डालीगंज, निरालानगर, जनपद लखनऊ–226020 से प्रकाशित।

सम्पादक– शक्ति सिंह मो0 7052608007 नोटः समाचार पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ न्यायालय होगा।